

[2023] 3 एस सी आर 1100

एमएएच। आदिवासी ठाकुर जमात स्वराक्षण समिति

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 2502)

24 मार्च, 2023

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और

मनोज मिश्रा, जे. जे.]

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने का विनियमन)

और) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000 का सत्यापन। 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9

महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति (जारी करने का विनियमन और

) प्रमाणपत्र नियम, 2003 आरआर का सत्यापन। 10 , 12 - महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग

(जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र नियम, 2012-क्या जाति प्रमाण पत्र को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए।

एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति के दावे पर निर्णय लेते समय आत्मीयता परीक्षण-दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या आत्मीयता परीक्षण जाति के दावे को तय करने के लिए एक लिटमस परीक्षण है-आयोजित: केवल तभी जब जांच समिति जांच करने के बाद समिति द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट न हो।

आवेदक, मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जा सकता है-मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को संदर्भित करते समय, जांच समिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं है-केवल एक मामले को जांच करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजे जाने के बाद, आत्मीयता परीक्षण के संचालन का अवसर उत्पन्न होगा-जब सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा एक आत्मीयता परीक्षण आयोजित किया जाता है, तो परीक्षण के परिणाम को प्रमाणिक मूल्य वाली रिकॉर्ड पर अन्य सभी सामग्री के साथ लेना होगा।

प्रत्येक मामले में जाति या जनजाति के दावे की शुद्धता का निर्धारण। महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े

1100 एमएएच। आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य

वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000-महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) प्रमाण पत्र नियम, 2003-महाराष्ट्र अनुसूचित जाति,

वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र नियम, 2012-क्या जाति जांच समिति अर्ध-न्यायिक कार्य करती है-आयोजित: 2000 के अधिनियम के तहत जांच समिति को सौंपा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की विभिन्न शक्तियां-शक्तियों में उपस्थिति को लागू करने की शक्ति शामिल है

कोई भी गवाह, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, गवाहों या दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आयोग जारी करने के लिए-2000 अधिनियम की योजना और एससी और एसटी दोनों नियमों में जांच का प्रावधान है।

शपथ पर आवेदक की जांच करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो आवेदक के जाति दावे की जांच करने वाली समिति, रिकॉर्डिंग

गवाहों का साक्ष्य और दस्तावेजों और अभिलेखों आदि के लिए बुलाना-जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के कारणों को जांच समिति से दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000 महाराष्ट्र

अनुसूचित जनजाति (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) प्रमाण पत्र नियम, 2003-महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े

वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र नियम, 2012-विजयकुमार बनाम में व्यक्त किए गए विचारों का टकराव था। महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। और आनंद बनाम। जनजाति दावों और अन्य की जांच और सत्यापन के लिए समिति। आत्मीयता परीक्षण के बारे में-आयोजित: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2000 के अधिनियम और नियमों पर विचार नहीं किया गया था, विजाकुमार के मामले में निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है

यह प्रस्ताव कि प्रत्येक मामले में, जांच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजकर आत्मीयता परीक्षण का सहारा लेना आवश्यक है-यह न्यायालय आनंद के मामले में दिए गए समान कारणों को दर्ज करता है कि आत्मीयता परीक्षण हमेशा अनिवार्य और/या निर्णायक नहीं होगा।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. 2000 के अधिनियम ने जाति के दावों के सत्यापन के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू की है। अभिव्यक्त भाषा को देखते हुए धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा उपयोग किया गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करता है

आवेदक का जाति दावा। जिस व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी जाति की स्थिति स्थापित हो गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा विचार की गई विस्तृत जांच के बाद ही उसमें बताई गई जाति का निर्णायक प्रमाण बन जाता है।

इस बात का संतोष कि उप-धारा द्वारा विचार किया गया जाति प्रमाण पत्र (1) धारा 4 जारी की जा सकती है। इसलिए, धारा 4 की उप-धारा (1) विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी से कारणों को दर्ज करने की अपेक्षा करती है।

आवेदन को अस्वीकार करने के लिए लेकिन जाति प्रमाण पत्र देते समय कारण देने की ऐसी कोई आवश्यकता शामिल नहीं है।

हालांकि, जाति जांच समिति से जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने और मान्य नहीं करने दोनों कारणों को दर्ज करने की उम्मीद है। एसटी नियमों के नियम 4 के उप-नियम (6) में प्रावधान है कि

सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित करेगा और यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेजों और साक्ष्य की शुद्धता से संतुष्ट है, तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। उक्त नियम के तहत निर्धारित समय सीमा भी एक संकेत है जो बताता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जाँच एक संक्षिप्त जाँच है और एक विस्तृत जाँच पर विचार नहीं किया गया है। 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पूरा नहीं किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी को विस्तृत जांच करनी है जो जांच द्वारा आयोजित की जानी चाहिए।

समिति। कानून जांच समिति द्वारा जाति के दावे की बहुत विस्तृत जांच पर विचार करता है। यदि सक्षम प्राधिकारी और जाति जांच समिति दोनों को एम. ए. एच. बनाना था।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, यह आवेदन को विद्यालय, गृह और अन्य जांच के संचालन के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजेगा। इसलिए, प्रत्येक मामले में, नियमित रूप से, जांच समिति यांत्रिक रूप से आवेदन को जांच करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को नहीं भेज सकती है। जब नियम 12 का उप-नियम (2) यह विचार करता है कि केवल तभी जब जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है कि मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जाना चाहिए, तो यह इस प्रकार है कि जांच समिति को दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होने के संक्षिप्त कारणों को दर्ज करते हुए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत। सतर्कता प्रकोष्ठ को मामला भेजने से पहले, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विवेक का प्रयोग आवश्यक है और इसलिए, विवेक का प्रयोग जांच समिति के आदेश पत्रों में परिलक्षित होना चाहिए। [पैरा 19] [1123-बी-डी]

3. जाँच समिति इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि आवेदक द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कानूनी जाँच करने के बाद। लेकिन यदि जांच समिति का विचार है कि आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित नहीं किया है कि जिस व्यक्ति को अभिलेख पर जाति वैधता प्रमाण पत्र दिया गया है, वह उसका रक्त संबंधी है, तो अनुसूचित जनजाति नियमों के नियम 12 के उप-नियम (2) के संदर्भ में, जाति जांच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से जांच करने के लिए भेजना होगा। ऐसे मामले में, सतर्कता प्रकोष्ठ को जांच समिति द्वारा संबंध [2023] 3 एस. सी. आर. तक सीमित जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक द्वारा उस व्यक्ति के साथ दावा किया गया है जिसके पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के आधार पर जांच समिति का मानना है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह आवेदक का रक्त संबंधी है और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कानूनी जांच की गई है, तो जांच समिति को वैधता प्रमाण पत्र जारी करना होगा, भले ही

आवेदक आत्मीयता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। [पैरा 23] [1125-सी-जी]

एफ़िनिटी टेस्ट

4. सतर्कता प्रकोष्ठ, एक आत्मीयता परीक्षण आयोजित करते समय, देवताओं के बारे में आवेदक के ज्ञान की पुष्टि करता है।

आवेदक दशकों से अपने परिवार के साथ बड़े शहरी क्षेत्रों में रहा है या यदि उसका परिवार दशकों से ऐसे शहरी क्षेत्रों में रहा है, तो आवेदक को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकती है। यह सच है कि सतर्कता प्रकोष्ठ भी पृष्ठताछ कर सकता है आवेदक के माता-पिता। लेकिन किसी मामले में, माता-पिता भी इस कारण से अनजान हो सकते हैं कि वे कई वर्षों से बड़े शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। दूसरी ओर, एक व्यक्ति विशेष जनजाति से संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन उसे उपरोक्त पहलुओं के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील, सही हैं जब उन्होंने प्रस्तुत किया कि आत्मीयता परीक्षण को लिटमस परीक्षण के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय यहां इस बात पर ध्यान दे सकता है कि आत्मीयता परीक्षण के संचालन का प्रश्न केवल उन मामलों में उत्पन्न होता है जहां जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं होती है। [पैरा 25] [1126-ई-जी]

एक-दूसरे को दोषी ठहराने की जाँच समिति

परफॉर्मिंग क्वासी-न्यायिक कार्य

5. 2000 के अधिनियम के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नियमों के संयुक्त अध्ययन पर, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि

जाँच समिति केवल प्रशासनिक कार्य करती है। 2000 के अधिनियम के तहत जांच समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की विभिन्न शक्तियां सौंपी गई हैं। इन शक्तियों में किसी भी गवाह की उपस्थिति को लागू करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, एम. ए. एच. को देने की शक्ति शामिल है।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य

गवाहों या दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आयोग जारी करना। 2000 के अधिनियम की योजना और एससी और एसटी दोनों नियमों में जांच समिति के लिए, यदि आवश्यक हो, शपथ पर आवेदक की जांच करने, गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और दस्तावेजों और रिकॉर्ड आदि के लिए बुलाने के बाद, आवेदक के जाति दावे पर जांच करने का प्रावधान है। उम्मीद की जाती है कि जांच समिति जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगी। इस प्रकार, जांच समिति के पास एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के सभी गुण हैं। [पैरा 28] [1128 - सी-एफ]

विजयकुमार के मामलों में निर्णय और

आनंद 6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2000 के अधिनियम और नियमों पर विचार नहीं किया गया था, विजयकुमार के मामले में निर्णय निश्चित रूप से नहीं है।

इस प्रस्ताव के लिए एक बाध्यकारी मिसाल है कि हर मामले में, जांच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजकर आत्मीयता परीक्षण का सहारा लेना आवश्यक है। [पैरा 29] [1129 सी-डी]

7. पैराग्राफ 4 और 5 में आनंद के मामले में निर्णय

विशेष रूप से एसटी नियमों के नियम 11 और 12 (2) को संदर्भित करता है। इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आनंद के पैराग्राफ 22 में पहले दिए गए समान कारणों को दर्ज किया कि आत्मीयता परीक्षण हमेशा अनिवार्य और/या निर्णायक नहीं होगा। [पैरा 30] [1129-डी; 1130-एफ-जी]

8. अब शिल्पा विष्णु ठाकुर के मामले में विवादित फैसले पर आते हैं। पूर्ण पीठ यह निर्धारित नहीं करती है कि हर मामले में

जहाँ जाँच समिति अनुसूचित जनजाति के दावे पर विचार कर रही है, वहाँ सतर्कता प्रकोष्ठ को एक संदर्भ दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ 40 के खंड (ii) (ए) में, पूर्ण पीठ ने दर्ज किया है कि जांच समिति को पूरे निकाय का ध्यान रखना चाहिए।

साक्ष्य, इस सवाल के साथ कि क्या आवेदक ने आत्मीयता परीक्षण को संतुष्ट किया है। जैसा कि पहले कहा गया था, आत्मीयता परीक्षण का सहारा लेने का सवाल तभी उठेगा जब मामला सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। वास्तव में, पैराग्राफ 40 के खंड (बी) में, पूर्ण पीठ का मानना है कि भले ही किसी आवेदक के पास कोई नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य वास्तव में जाति के दावे को अमान्य नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले में नियम 12 का उप-नियम (2) लागू होगा और सतर्कता प्रकोष्ठ को एक [2023] 3 एस. सी. आर. आयोजित करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ के खंड (2) में किसी भी तरह से निर्णायक नहीं होगा 20 आनंद के मामले में। उसी पैराग्राफ के खंड (सी) में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का यह भी मानना है कि भले ही आवेदक

अभिलेख पर साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर, आत्मीयता परीक्षण को आंशिक रूप से संतुष्ट करता है, जांच समिति के पास दावे को मान्य करने की शक्ति है। इस प्रकार, सम खंड (ग) आधार पर आगे बढ़ता है

कि आत्मीयता परीक्षण निर्णायक नहीं है। [पैरा 34] [1132-डी-एच; 1133 ए]

निष्कर्ष

9. इस

प्रकार, निष्कर्ष निकालने के लिए, यह न्यायालय मानता है कि:

सतर्कता प्रकोष्ठ के मामले में, जांच समिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए कि वह इससे संतुष्ट नहीं है आवेदक द्वारा उत्पादित सामग्री। जाँच के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को मामला भेजे जाने के बाद ही आत्मीयता परीक्षण के संचालन का अवसर उत्पन्न होगा।

जाति वैधता दावे पर निर्णय लेने के लिए जांच समिति द्वारा विचार; (ग) संक्षेप में, आत्मीयता परीक्षण जाति के दावे को तय करने के लिए एक लिटमस परीक्षण नहीं है और जाति के दावे की प्रक्रिया में एक आवश्यक हिस्सा नहीं है।

प्रत्येक मामले में जाति या जनजाति के दावे की शुद्धता का निर्धारण। [पैरा 36] [1133-सी-जी]

कुमारी माधुरी पाटिल और एक अन्य वी.

एडल्ट। आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य

(1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3 पूरका एस. सी. आर. 50; आनंद बनाम जनजाति के दावों की जांच और सत्यापन के लिए समिति & ओआरएस। (2012) 1 एससीसी 113: [2011] 15 एस. सी. आर. 386; जिला कलेक्टर, सतारा और अन्न। वी. मंगेश निवृत्ति काशीद

(2019) 10 एससीसी 166: [2019] 15 एससीआर 685-पर निर्भर। पालघाट जिला थंडन समुद्र संरक्षण समिति और अन्न। वी. केरल राज्य (1994) 1 एस. सी. सी. 359: [1993] 3 एमएएच।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य

पूरक। एस. सी. आर. 872; महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. रवि

प्रकाश बाबूलालसिंह परमार और अन्न। (2007) 1 एससीसी 80

चित्रा वी. जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, राज्य स्तर
सतर्कता समिति, तमिलनाडु और अन्य। (2021) 9 एससीसी

811 संदर्भित किया गया।

विजाकुमार बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2010) 14

एस. सी. सी. 489 एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है।
शिल्पा विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2009 (3)

Mh.LJ (एफ. बी.) 995; अपूर्व डी/ओ विनय निकोल बनाम।

प्रभागीय समिति 2010 (6) Mh.LJ-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 3 पूरक। एससीआर 50

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2011] 15 एससीआर 386

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2019] 15 एससीआर 685

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[1993] 3 पूरक। एससीआर 872

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

शेखर नाफडे, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, संजय आर. हेगड़े, श्रीमती. मीनाक्षी अरोड़ा, श्याम दीवान, आर. बाला, एम. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत जोसेफ, विवेक सी. सोलशे, वरुण वी. सोलशे, अंजनी कुमार झा, अभिजीत सिन्हा, मेसर्स। लैम्बर्ट एंड एसोसिएट्स, शाश्वत गोयल, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, विजय राज सिंह चौहान, अंश देशपांडे, [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धार्थ गौतम, गजानन एन. तीर्थकर, रामेश्वर प्रसाद गोयल, गगन सांघी, सुश्री अश्वारिया दास, डॉ. प्रशांत प्रताप, चंदर शेखर अशरी, अमलान कुमार घोष, सुश्री प्रीति राणे, आशीष पांडे, अपूर्व

श्रीवास्तव, शिरीष के. देशपांडे, सुश्री रुचा प्रवीण मंडलिक, मोहित गौतम, शाहरुख अली, अनंत रामटेके, राहुल शर्मा, सुधांशु एस. चौधरी, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, एम. वीरारागवन, सुश्री फराह हाशमी, सुश्री ऐश्वर्या दास, आर. पी. गुप्ता, आनंद सुकुमार, क्षितिज मित्तल, एस. सुकुमारन, भूपेश कुमार पाठक, सुश्री मीरा माथुर, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सचिन पाटिल, सुश्री मयूरी।

रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सुश्री आकांक्षा राठौर, योगेश मलिक, रवींद्र केशवराव अदसुरे, प्रवीण पाटिल, सिद्धेश्वर नामदेव बिरादर, यश प्रशांत सोनावने, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, निकलेश रामचंद्रन, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री विमला सिन्हा, अनमोल चंदन, उदय खन्ना, प्रतीक आर. बॉम्बार्डे, सुभाष कुमार, धर्म दत्ता वर्मा, अभिषेक कुमार, गोपाल बलवंत साठे, मैसर्स। ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर, सुहासकुमार कदम, भार्गव वी. देसाई, राहुल गुप्ता, सिद्धार्थ चौधरी, उत्कर्ष वत्स, दीपांशु, सुश्री भारती त्यागी, जे. एन. सिंह, सौरभ मिश्रा, श्रीमती साधना सिंह, अभिषेक सिंह, सुश्री प्रिया कौशिक, सुदर्शन मेनन, समरेंद्र बेउरा, राजेश राठौर, सुश्री उषा रानी प्रधान, अजय

कुमार भाटिया, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री पल्लवी शर्मा, गौरव अग्रवाल, अमोल बी. करंडे, महेश बी. करंडे, नरेंद्र राव ठाणेयर, सुश्री जसवंती, सुश्री आइना वर्मा, नितिन मेशराम, नारायण जंभूले, रितेश पाटिल, रणवीर सिंह यादव, अभिजीत एस. कांबले, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, सुश्री निहारिका देवीवेदी, नरेंद्र पाल शर्मा, अमित कुमार चावला, रवीश कुमार गोयल, माधवी एस. सावंत, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

प्रेलूड

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की एक सूची को संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

आदेश, 1950 (संक्षेप में 'एसटी आदेश')। 1976 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, एसटी आदेश में संशोधन किया गया था। 1976 के अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग IX में महाराष्ट्र राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की एक सूची है। प्रवेश संख्या. 44 महाराष्ट्र सूची में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है:

एमएएच। आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

“ ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर, मा ठाकुर,

मा ठाकर ”।

2. जाति के दावों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दे बड़ी संख्या में मामलों में सामने आए। में

कुमारी माधुरी पाटिल का मामला और एक अन्य बनाम। एडल्ट। आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य, इस न्यायालय ने नोट किया कि यह आवश्यक था

सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, उनकी जांच और उनकी मंजूरी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि कई मामलों में देखा गया कि उम्मीदवारों ने झूठे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्रों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया, जिसका अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित वास्तविक उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित करने का प्रभाव पड़ा। जाति की स्थिति के सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई कानून उस समय लागू नहीं था। इसलिए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 में बहुत व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 13 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“ 13. गलत तरीके से प्राप्त या गलत तरीके से नियुक्ति

यह आवश्यक है कि जारी किए गए प्रमाणपत्रों की जल्द से जल्द और अत्यधिक अभियान और शीघ्रता के साथ जांच की जाए। उस उद्देश्य के लिए, सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, उनकी जांच और उनकी मंजूरी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन राजस्व उप-मंडल अधिकारी और उप-क्लेक्टर को किया जाएगा।

1 (1994) 6 एससीसी 241 [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या उपायुक्त और प्रमाण पत्र अधिकारी, तालुक या मंडल स्तर के बजाय ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

2. माता-पिता, अभिभावक या उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, एक सक्षम राजपत्रित अधिकारी या गैर-राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाति और उप-जाति, जनजाति, आदिवासी समुदाय, जनजातियों या आदिवासी समुदायों के हिस्सों या समूहों के विवरण के साथ विधिवत शपथ और सत्यापित एक हलफनामा दायर करेगा, जिस स्थान से वह मूल रूप से आता है।

से और अन्य विवरण जो संबंधित निदेशालय द्वारा निर्धारित किए जाएं। 3. जाँच समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आवेदन शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या किसी पद पर नियुक्ति से पहले कम से कम छह महीने पहले दाखिल किया जाएगा।

4. सभी राज्य सरकारें तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगी, अर्थात् (1) एक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव या संबंधित विभाग के निदेशक के पद का कोई उच्च अधिकारी, (2) निदेशक, समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण/पिछड़ा वर्ग।

कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (III) अनुसूचित जातियों के मामले में एक अन्य अधिकारी जिसे मामले में अंतरंग जानकारी है।

सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों का सत्यापन और जारी करना। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अनुसंधान अधिकारी जिनके पास है

जनजातियों, जनजातीय समुदायों, जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों की पहचान करने में अंतरंग ज्ञान।

5. प्रत्येक निदेशालय को एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए जिसमें सामाजिक स्थिति के दावों की जांच करने के लिए सभी प्रभागों में वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक और इतनी संख्या में पुलिस निरीक्षक शामिल हों। निरीक्षक उस स्थानीय निवास स्थान और मूल स्थान पर जाता था जहाँ से उम्मीदवार रहता है और आमतौर पर रहता है या उस शहर या शहर में प्रवास के मामले में, जहाँ से वह मूल रूप से आया था। सतर्कता अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सभी का सत्यापन और संग्रह करना चाहिए।

उम्मीदवार या माता-पिता या अभिभावक द्वारा दावा की गई सामाजिक स्थिति के तथ्य, जैसा भी मामला हो। उसे स्कूल की भी जांच करनी चाहिए। अभिलेख, जन्म पंजीकरण, यदि कोई हो। उसे माता-पिता, अभिभावक या उम्मीदवार से उनकी जाति आदि के संबंध में या ऐसे अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ करनी चाहिए जिन्हें उम्मीदवार की सामाजिक स्थिति का ज्ञान है और फिर एच. आदिवासी ठाकुर जमात स्वर्ण समिति बनाम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

जैसा कि परिकल्पना की गई है, सभी विवरणों के साथ निदेशालय विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के उनके विशिष्ट मानवशास्त्रीय और नृजातीय लक्षणों से संबंधित,

संबंधित जातियों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों द्वारा देवता, अनुष्ठान, रीति-रिवाज, विवाह का तरीका, मृत्यु समारोह, शवों को दफनाने का तरीका आदि।

6. संबंधित निदेशक, सतर्कता अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर यदि वह सामाजिक स्थिति के दावे को "वास्तविक नहीं" या "संदिग्ध" या नकली या गलत या गलत तरीके से दावा किया गया पाता है, तो संबंधित निदेशक को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार को सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति की जाए।

देय पावती के साथ या संबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के माध्यम से पंजीकृत पद जिसमें उम्मीदवार पढ़ रहा है या कार्यरत है। नोटिस में यह संकेत दिया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन या जवाब, यदि कोई हो, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर और किसी भी मामले में अनुरोध पर नहीं किया जाएगा। नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक नहीं। यदि उम्मीदवार सुनवाई का अवसर चाहता है और उस ओर से जांच किए जाने का दावा करता है, तो निदेशक इस तरह के अभ्यावेदन/उत्तर की प्राप्ति पर समिति और संयुक्त/अतिरिक्त सचिव को अध्यक्ष के रूप में बुलाएगा।

उम्मीदवार/माता-पिता/अभिभावक को अपने दावे के समर्थन में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर। ढोल बजाकर या किसी अन्य सुविधाजनक तरीके से गाँव या इलाके में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा सकती है और यदि कोई व्यक्ति या संघ ऐसे दावे का विरोध करता है, तो उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से ऐसा अवसर देते हुए, समिति ऐसी जांच कर सकती है जो उसे समीचीन लगे और उम्मीदवार या प्रतिद्वंद्वी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के दावों पर विचार कर सकती है और संक्षिप्त कारणों के साथ एक उचित आदेश पारित कर सकती है।

इसका समर्थन करें।

7. यदि रिपोर्ट उम्मीदवार के पक्ष में है और पाई जाती है

वास्तविक और सत्य, इसके अलावा कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि रिपोर्ट या दिए गए विवरण प्राप्त किए गए हैं या गलत या धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए पाए गए हैं और बाद की स्थिति में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जैसा कि पैरा 6 में परिकल्पित है।

8. पैरा 6 में अनुध्यात सूचना माता-पिता/अभिभावक को भी जारी की जानी चाहिए यदि उम्मीदवार नाबालिग है तो [2023] 3 एस. सी. आर. के समक्ष उपस्थित होने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावे के समर्थन में सभी सबूतों के साथ समिति

सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों के लिए।

9.

.....

10.

11. समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम और निर्णायक होगा।

केवल अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही के अधीन
संविधान।

12. किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
झूठ बोलते हैं। "

(जोर

दिया गया)

3. उपरोक्त दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से तैयार किए गए थे

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग क्योंकि इस न्यायालय ने पाया कि इस क्षेत्र में कोई कानून नहीं चल रहा था। जहाँ तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, 18 अक्टूबर 2001 से महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति

प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 (संक्षेप में '2000 अधिनियम') को लागू किया गया था। 2000 के अधिनियम में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन को विनियमित करने के लिए एक बहुत ही विस्तृत तंत्र शामिल है।

पिछड़े वर्गों की श्रेणियाँ। एक दो-स्तरीय तंत्र प्रदान किया गया था। पहला स्तर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का है जो 2000 के अधिनियम के तहत गठित जांच समिति द्वारा सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र के अनुदान के अधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए धारा 6 के तहत गठित जांच समिति में शक्ति निहित है। धारा 9 सक्षम प्राधिकारी और सिविल न्यायालय की जांच समिति को गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने, दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी भी न्यायालय या कार्यालय से इसकी प्रति की मांग करने और गवाहों की परीक्षा या दस्तावेजों को पेश करने के लिए आयोग जारी करने की शक्तियां प्रदान करती है। नियम

महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति (जारी करने और सत्यापन का विनियमन)) प्रमाण पत्र नियम,
2003 (संक्षेप में "एसटी नियम")। इसी तरह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, (विमुक्त
जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े एम. ए. एच.।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

श्रेणी (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र

नियम, 2012 (संक्षेप में 'अनुसूचित जाति नियम') बनाए गए थे। जाँच समिति के गठन के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी और जाँच समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत प्रावधान दोनों श्रेणियों पर लागू नियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति नियमों के नियम 10 और नियम 12 में जाँच करने के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जाँच समितियों की सहायता के लिए सतर्कता प्रकोष्ठों के गठन का प्रावधान है। एसटी नियमों के तहत स्थापित सतर्कता प्रकोष्ठ में एक वरिष्ठ उप-सचिव होता है

पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस कांस्टेबल सहायता करेंगे

पुलिस निरीक्षक और एक अनुसंधान अधिकारी। एससी नियम विशेष रूप से सतर्कता प्रकोष्ठ के लिए आत्मीयता परीक्षण आयोजित करने का प्रावधान करते हैं। इस बात को लेकर कुछ विवाद है कि क्या एसटी के तहत सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है

संबंधित जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय। आत्मीयता परीक्षण के एक भाग के रूप में, एक उम्मीदवार जिसने सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है कि क्या उसे विशेष जाति/जनजाति से संबंधित उपरोक्त कारकों के बारे में जानकारी है।

नियंत्रण

4. 24 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार, मामलों का वर्तमान समूह

एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। मुख्य मामले (2022 की दीवानी अपील संख्या 2502) में चुनौती शिल्पा विष्णु ठाकुरव के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को दी गई है। की स्थिति

महाराष्ट्र 2. बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 2000 के अधिनियम के साथ-साथ एसटी नियमों के प्रावधानों की व्याख्या की है। विवादित निर्णय जाँच समिति द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं पर चर्चा करता है और निर्धारित करता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना है कि आत्मीयता परीक्षण का एक अभिन्न अंग है

जाति के दावे की शुद्धता का निर्धारण। 24 मार्च 2022 के आदेश में, इस न्यायालय की एक पीठ ने उल्लेख किया कि इस न्यायालय की समन्वय पीठों के दो निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों का टकराव था। पहला मामला विजाकुमार बनाम का है। महाराष्ट्र राज्य & Ors.³ और दूसरा मामला आनंद बनाम का है। जाँच समिति और

2 2009 (3) Mh.LJ (F. B.) 995
एस. सी. आर.

3 (2010) 14 एससीसी489 [2023] 3

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनजाति के दावों का सत्यापन & Ors.4। विजाकुमार 3 के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 9 में, इस अदालत ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी स्तर पर आत्मीयता परीक्षण में विफल रहता है, तो उसे जाति वैधता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है।

उसे। आनंद के मामले में, यह माना गया था कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति के दावे को तय करने के लिए आत्मीयता परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं है। यह माना गया कि इसका उपयोग दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। तय किया जाने वाला सवाल यह है कि क्या

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति के दावे पर निर्णय लेते समय आत्मीयता परीक्षण को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या

आत्मीयता परीक्षण जाति के दावे को तय करने के लिए एक लिटमस परीक्षण है।

दलों की सामग्री

5. श्री शेखर नाफडे द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 2502 में अपीलार्थियों की ओर से मुख्य प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।

वरिष्ठ वकील। उन्होंने हमें 2000 के अधिनियम और एसटी नियमों के माध्यम से ले जाया है। कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा, आग्रह किया कि संविधान से पहले की अवधि से संबंधित दस्तावेजों का सबसे अधिक संभावित मूल्य है। वह प्रस्तुत करता है कि यदि जाति के दावे के समर्थन में ऐसे दस्तावेज जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं,

और यदि वे प्रासंगिक और वास्तविक पाए जाते हैं, तो जांच समिति के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से जांच का आदेश देने का कोई अवसर नहीं है। इसी तरह, यदि जाति जांच समिति के समक्ष सत्यापन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के रक्त रिश्तेदारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र दिए गए हैं, तो जांच समिति द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जाती है। दोनों ही मामलों में जाति प्रमाण पत्र को मान्य करना जाति जांच समिति का कर्तव्य है। उन्होंने एसटी नियमों के नियम 12 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो जांच समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि उप-नियम (2) में प्रावधान है कि यदि जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से जांच का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि आत्मीयता परीक्षण के संचालन का सवाल तभी उठता है जब मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जाता है जब जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाति के दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच समिति यंत्रवत रूप से किसी मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को इस संतोष को दर्ज किए बिना नहीं भेज सकती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कास्टक्लेम को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

4 (2012) 1 एस. सी. सी. 113 एमएएच.

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनामा। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

6. उन्होंने अपूर्व डी/ओ विनय निकोल बनाम के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। प्रभागीय समितियाँ। वह.

प्रस्तुत किया कि यदि कोई आवेदक संविधान पूर्व अवधि से संबंधित दस्तावेजों या अपने रक्त संबंधी को दिए गए प्रमाणिक मूल्य या जाति वैधता प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों के आधार पर अपने जाति के दावे को सफलतापूर्वक स्थापित करता है, तो आत्मीयता परीक्षण लागू करना आवश्यक नहीं है। संक्षेप में, उनका निवेदन है कि आत्मीयता परीक्षण एक लिटमस परीक्षण नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आनंद के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 2000 के अधिनियम और एसटी नियमों की व्याख्या पर आधारित है। उन्होंने बताया कि एस. टी. नियम लागू होने से पहले विजकुमार के 3 मामलों का फैसला इस अदालत ने किया है। वह आग्रह करेंगे कि निर्णय में यह सुझाव देने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं हैं कि हर मामले में आत्मीयता परीक्षण अनिवार्य है। विद्वान वकील ने जिला कलेक्टर, सतारा और अन्न के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए दबाव डाला। वी. मंगेश निवृत्ति

काशीद '। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक मामले में सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल तभी है जब जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि एक आवेदक जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और जो शहरी क्षेत्र में रह रहा है, वह ऐसा नहीं कर सकता है

जनजाति के लक्षणों, विशेषताओं, समारोहों और देवताओं से परिचित रहें। विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2005 की 1 अगस्त 2018 की रिट याचिका No.4198 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया,

जिसका मानना है कि आनंद * के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, शिल्पा विष्णु ठाकुर 2 के मामले में विवादित फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि विवादित निर्णय में संशोधन की आवश्यकता है और यह माना जाना चाहिए कि जाति के दावे का निर्णय करते समय आत्मीयता परीक्षण का सर्वोच्च महत्व नहीं है।

5 2010 (6) Mh.LJ पृष्ठ 401

6 (2019) 10 एससीसी 166

7 (1994) 1 एससीसी 359 [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार। उनका निवेदन है कि यदि किसी मामले में संभावित मूल्य वाले दस्तावेजों से पता चलता है कि आवेदक ठाकुर जाति से संबंधित है या 1976 के अधिनियम की तीसरी अनुसूची में अधिसूचित किसी अन्य जाति से संबंधित है, तो कोई आत्मीयता परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है।

8. महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने बताया कि यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि उपनाम ठाकुर अग्रगामी और पिछड़े दोनों वर्गों द्वारा साझा किया जाता है।

समुदाय। उन्होंने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा। वी. रवि प्रकाश बाबूलालसिंह परमार और Anr.8 उन्होंने कहा कि विवादित फैसले में भी इस तथ्यात्मक पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत तीन चरणों में जांच की आवश्यकता है। पहला यह पता लगाने के लिए एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा की गई जांच है कि

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उसके दावे की वास्तविकता। यदि प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों से संतुष्ट है, तो उसे एक जाति प्रमाण पत्र जारी करना होगा जो सत्यापन के अधीन है। दूसरा चरण सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा संचालित घरेलू और विद्यालय जांच का है जिसमें एक आत्मीयता परीक्षण शामिल होगा और तीसरा चरण जांच समिति द्वारा सत्यापन और जांच का है जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।

9. उनके द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, उन्होंने तर्क दिया है कि भले ही वैधता प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा जारी किए गए हों

आवेदक के निकट रिश्तेदारों के मामले में, जांच समिति को फिर से पूरे साक्ष्य का आकलन करने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में एक आत्मीयता परीक्षण लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैधता कायम न रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां किसी करीबी रिश्तेदार को गलती या धोखाधड़ी से या कानून द्वारा विचार किए बिना या कोई कारण दर्ज किए बिना वैधता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच समिति इस सवाल पर भी विचार कर सकती है कि क्या पहले का वैधता प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय के गलत आदेश के आधार पर जारी किया गया है। आनंद के मामले में निर्णय में पैराग्राफ 22.1 में जो कहा गया है, वह गलत है।

10. राज्य सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में, आवेदक लक्षणों से पूरी तरह से परिचित नहीं हो सकता है,

जनजाति या देवताओं आदि के धार्मिक समारोह। इसलिए, सतर्कता

8 (2007) 1 एससीसी 80 एमएच।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

प्रकोष्ठ को आवेदक के माता-पिता की भी जांच करने की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने आग्रह किया कि अनुसूचित जनजाति ठाकुर के मामले में एक अलग परीक्षा लागू होगी क्योंकि इस उपनाम वाले व्यक्ति भी अग्रिम वर्गों के हैं। इसलिए, ठाकुर के जनजाति के दावे के मामले में, उम्मीदवार के उपनाम ठाकुर वाले संविधान पूर्व दस्तावेजों का कोई परिणाम नहीं है। इसलिए, जनजाति के दावे के मामले में

ठाकुर, एक आत्मीयता परीक्षण लागू करना होगा। राज्य का निवेदन है कि विजाकुमार 3 के मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही और आवश्यक है।

2000 के अधिनियम के तहत गठित एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण नहीं है। वह. प्रस्तुत किया कि दयाराम बनाम के मामले में। सुधीर बाथम और अन्य "। , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जांच समिति एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जे. चित्रा बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा 'दयाराम' के मामले में निर्णय का पालन किया गया है। जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति,

तमिलनाडु और Ors.¹⁰ उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि आत्मीयता परीक्षण जांच समिति द्वारा जांच का एक अभिन्न अंग है, का कोई कानूनी आधार नहीं है। उनका कहना है कि आनंद के मामले का सही निर्णय लिया गया है और उस हद तक शिल्पा विष्णु ठाकुर 2 के मामले में विवादित फैसले को संशोधित करना होगा।

हस्तक्षेप करने वालों में से एक ने एससी नियमों के प्रावधानों पर भी भरोसा किया और कहा कि हालांकि यह विशेष रूप से सतर्कता को सशक्त बनाता है

आत्मीयता परीक्षण करने के लिए प्रकोष्ठ, ऐसा प्रावधान एसटी नियमों में अनुपस्थित है।

हमारा दृष्टिकोण

12. हम कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का विस्तार से उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। ए. को. दयारामो के मामले में अध्यादेश पीठ ने अपने फैसले के पैराग्राफ 35 में कहा कि इस अदालत द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल के मामले 1 के पैराग्राफ 13 में जारी किए गए निर्देश जारी किए गए थे क्योंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के जाति दावों के सत्यापन के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुमारी माधुरी पाटिल 1 के मामले में जारी किए गए निर्देश केवल तब तक लागू होंगे जब तक कि उचित कानून लागू नहीं किया जाता है। अतः इसके बाद

9 (2012) 1 एससीसी 333
आर.

10 (2021) 9 एससीसी 811 [2023] 3 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2000 का अधिनियम लागू हुआ, केवल उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे।

13. इसलिए, हमें 2000 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी। 2000 का अधिनियम 18 अक्टूबर 2001 को लागू हुआ। जैसा हो सकता है। शीर्षक से देखा गया है कि 2000 का अधिनियम संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के विनियमन से संबंधित है।

अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग। 2000 अधिनियम की योजना के तहत, धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी को नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उम्मीदवार द्वारा किया गया दावा वास्तविक है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। धारा 4 की उप-धारा (1), अच्छे कारणों से, विशेष रूप से प्रदान करती है कि यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि जाति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश को धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत अपील योग्य बनाया गया है, इसलिए अपीलीय प्राधिकरण को अस्वीकृति के कारणों का लाभ मिलना चाहिए।

14. धारा 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण

और जांच समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को लागू करने और शपथ पर उसकी जांच करने, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी भी न्यायालय या कार्यालय से उसकी प्रति की मांग करने और गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करने की सिविल अदालत की शक्तियां दी गई हैं। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी और जांच समिति द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति और विस्तार अलग-अलग है। 2000 के अधिनियम ने जाति के दावों के सत्यापन के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू की है। द्वारा उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा को देखते हुए धारा 4 की उप-धारा (2), सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदक के जाति दावे को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करता है। जिस व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी जाति की स्थिति स्थापित हो गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा विचार की गई विस्तृत जांच के बाद ही उसमें बताई गई जाति का निर्णायक प्रमाण बन जाता है और प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा बनाया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। इसलिए, जब एमएएच।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

जाति प्रमाण पत्र देने के लिए धारा 3 के तहत किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री की बहुत विस्तृत जांच पर विचार नहीं किया जाता है। जिस पर विचार किया जाता है वह जाति के दावे की वास्तविकता की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है और इस तरह की संतुष्टि के आधार पर कि एक जाति प्रमाण पत्र

धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात जारी किया जा सकता है। इसलिए, धारा 4 की उप-धारा (1) विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी से आवेदन को अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने की अपेक्षा करती है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है।

जाति प्रमाण पत्र प्रदान करते समय कारण देने की आवश्यकता शामिल है। हालांकि, जाति जांच समिति से जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने और मान्य नहीं करने दोनों कारणों को दर्ज करने की उम्मीद है। एसटी नियमों के नियम 4 के उप नियम (6) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित करेगा और यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेजों और साक्ष्य की शुद्धता से संतुष्ट है, तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। उक्त नियम के तहत निर्धारित समय सीमा भी एक संकेत है जो बताता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच एक संक्षिप्त जांच है और एक विस्तृत जांच पर विचार नहीं किया गया है। द.

15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पूरा नहीं किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी को जांच समिति द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच के बराबर विस्तृत जांच करनी है।

जाति जांच समिति को जाति के दावों की समान स्तर की जांच और विस्तृत जांच करनी थी, जिससे दो-स्तरीय जांच का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। धारा 8 में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी और जांच समिति के समक्ष जाति के दावे को साबित करने का भार आवेदक पर है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उक्त भार का निर्वहन करने के लिए, यह पर्याप्त है यदि आवेदक प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है कि उसका जाति का दावा वास्तविक है। धारा 8 द्वारा आवेदक पर जांच समिति के समक्ष अपनी जाति की स्थिति साबित करने का बोझ डाला गया है - सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वहन करने के लिए आवश्यक बोझ से बहुत अधिक।

16. धारा 10 की उप-धारा (1) में विचार किया गया है कि यदि कोई आवेदक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाँच [2023] 3 एस. सी. आर. द्वारा जाति प्रमाण पत्र के रद्द होने पर, किसी शैक्षणिक संस्थान में रोजगार या प्रवेश जैसे किसी भी लाभ को प्राप्त करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति, शैक्षणिक संस्थान या रोजगार में प्राप्त प्रवेश को तुरंत रद्द करना आवश्यक है। खंड की योजना 10 यह है कि आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किसी भी लाभ को अपने पास नहीं रख सकता है जिसे बाद में जांच समिति द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

17. धारा 6 जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए जाति जांच समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। उप-खंड

(4) धारा 6 में कहा गया है कि जांच समिति 2000 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। एसटी नियमों का नियम 4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि नियम 10 के तहत अनुसूचित जनजाति जाति की सहायता के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान किया गया है जांच करने में जांच समिति। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सतर्कता प्रकोष्ठ में तीन अलग-अलग रैंकों के पुलिस अधिकारी और एक अनुसंधान अधिकारी होते हैं। नियम 11 उन दस्तावेजों का विवरण प्रदान करता है जिन्हें आवेदक को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए जमा करना होगा। नियम 11 के उप-नियम 2 और 3 इस प्रकार हैं:

“ 11. (1) ”

(2) आवेदक अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा।

: ! .

(क) मूल दस्तावेज।

(i) एक सत्यापित प्रति के साथ आवेदक का मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र,

((ii) फॉर्म एफ में एक शपथ पत्र;

(ख)

जिन दस्तावेजों की केवल सत्यापित प्रतियां होनी चाहिए

आवेदक के संबंध में प्रस्तुत किया गया

(i) प्राथमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।

((ii) विद्यालय प्रवेश रजिस्टर का एक उद्धरण।

(iii) जन्म रजिस्टर का एक उद्धरण।

पिता के संबंध में दस्तावेज, -

((ग)

((i) जन्म रजिस्टर का एक उद्धरण।

((ii) प्राथमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।

एच. आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

(iii) विद्यालय प्रवेश रजिस्टर का सारा।

(iv) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।

(v) यदि कोई पिता सेवा में है, तो सेवा अभिलेख (पुस्तक) के पृष्ठों का उद्धरण जिसमें धर्म और जनजाति प्रविष्टि शामिल है।

(vi) यदि कोई पिता अनपढ़ है, तो आवेदक के पैतृक पक्ष के वास्तविक बुजुर्ग रक्त रिश्तेदारों का प्राथमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और विद्यालय का सारा।

प्रवेश रजिस्टर।

(घ) अन्य दस्तावेज,

(i) राजस्व रिकॉर्ड जैसे, जन्म रजिस्टर, 7/12 का उद्धरण,

विक्रय विलेख आदि।

(ii) उसके समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

अनुसूचित जनजाति का दावा।

(iii) उन निकट रिश्तेदारों के शपथ पत्र जिनकी वैधता प्रमाण पत्र आवेदक के अनुसूचित जनजाति के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(3) जब भी जांच समिति द्वारा आवश्यक हो, आवेदक सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज जमा करेगा।

18. नियम 12 जाँच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

कुछ नहीं। इसमें एक मामले को अग्रेषित करने के संबंध में एक प्रावधान है

जांच करने के लिए प्रकोष्ठ। नियम 12 इस प्रकार है:

(1) आवेदन की प्राप्ति पर, जांच समिति या इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवेदन की जांच करेगा, आवेदन का सत्यापन करेगा।

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज, और आवेदन की प्राप्ति को स्वीकार करें। सदस्य सचिव

सत्यापन के लिए प्राप्त आवेदन को-रजिस्टर में पंजीकृत करेगा।

सभापति द्वारा विहित।

(2) यदि जांच समिति संतुष्ट नहीं है

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

जाँच समिति आवेदनों को भेजेगी

विद्यालय, गृह और अन्य के संचालन के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ

पृथक्ताछ की।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) सतर्कता अधिकारी उस स्थानीय निवास स्थान और मूल स्थान पर जाएगा जहाँ से आवेदक रहता है और आमतौर पर रहता है, या प्रवास के मामले में, उस शहर या शहर या स्थान पर जाएगा जहाँ से वह मूल रूप से आया था।

(4) सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आवेदक द्वारा दावा की गई सामाजिक स्थिति के बारे में सभी तथ्यों का सत्यापन और संग्रह करेगा।

या उसके माता-पिता या अभिभावक, जैसा भी मामला हो।

(5) सतर्कता प्रकोष्ठ आवेदक के माता-पिता या अभिभावक या आवेदक की उनकी जनजाति के सत्यापन के उद्देश्य से भी जांच करेगा। (6) जाँच पूरी होने के बाद, सतर्कता प्रकोष्ठ अपनी रिपोर्ट जाँच समिति को सौंपेगा जो बदले में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करेगी।

(7) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में है, और यदि जांच समिति संतुष्ट है कि

आवेदक वास्तविक और सच्चा है, जांच समिति वैधता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। वैधता प्रमाण पत्र फॉर्म जी में जारी किया जाएगा।

(8) यदि जांच समिति, सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट और उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर, इस बारे में संतुष्ट नहीं है आवेदक के दावे पर समिति आवेदक को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करेगी। और सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा देय पावती के साथ भी भेजे। यदि आवश्यक हो तो एक प्रति संबंधित विभाग के प्रमुख को भी भेजी जाएगी। नोटिस इंगित करेगा कि अभ्यावेदन या जवाब, यदि कोई हो, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं।

सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों से अधिक। यदि आवेदक समय सीमा के स्थगन या विस्तार के लिए अनुरोध करता है, तो उचित समय दिया जा सकता है।

(9) (क) व्यक्तिगत सुनवाई के बाद यदि जांच समिति दावे की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है, तो वैधता प्रमाण पत्र फॉर्म जी में जारी किया जाएगा।

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, यदि जांच समिति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के दावे की वास्तविकता और शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह एमएएच का आदेश पारित करेगी।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

रद्द करना और ज़ब्त करना। प्रमाणपत्र और

इसे लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए। अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र पर तब "रद्द और ज़ब्त" के रूप में मुहर लगाई जाएगी।

19. नियम 12 के उप-नियम (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं होने पर ही

आवेदन को जाँच करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजें। जब नियम 12 का उप-नियम (2) यह विचार करता है कि केवल तभी जब जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है कि मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जाना चाहिए, तो यह इस प्रकार है कि जांच समिति को संक्षिप्त कारणों को दर्ज करते हुए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट क्यों नहीं है। इससे पहले मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को संदर्भित करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विवेक का उपयोग आवश्यक है और इसलिए, विवेक का उपयोग जांच समिति के आदेश पत्रों में परिलक्षित होना चाहिए।

20. यह पूरी तरह से निर्धारित करना संभव नहीं है कि किन मामलों में जांच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजना चाहिए। इनमें से एक

कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। यह बताता है कि पूर्व-संविधान अवधि के दस्तावेजों से पता चलता है कि आवेदक और उनके पूर्वजों की जाति को सबसे अधिक संभावना मिली है।

मूल्या। उदाहरण के लिए, यदि कोई आवेदक संविधान पूर्व अवधि के प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम है, जो दर्शाता है कि वह एक आदिवासी समुदाय से है, तो उसके दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि 1950 से पहले, अनुसूचित जनजातियों में शामिल जनजातियों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

आदेश दें। ऐसे मामले में सतर्कता प्रकोष्ठ को संदर्भित करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। 21. 2022 की सिविल अपील संख्या 2502 (शिल्पा विष्णु ठाकुर का मामला 2) में विवादित फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा,

अदालत ने नोट किया है कि "ठाकुर" उपनाम वाले लोग अगड़ी जातियों और विभिन्न पिछड़ी जातियों दोनों से संबंधित हैं। इसलिए, पूर्ण पीठ का यह कहना सही हो सकता है कि प्रत्येक मामले में, केवल उपनाम ठाकुर के आधार पर, जांच समिति द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आवेदक महाराष्ट्र सूची की प्रविष्टि 44 में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति ठाकुर से संबंधित है। हालाँकि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि [2023] 3 एस. सी. आर. के मामले में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सतर्कता प्रकोष्ठ को मामला। यह सब जाति जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रकृति और दस्तावेजों के संभावित मूल्य पर निर्भर करता है। इसलिए, जब भी ठाकुर अनुसूचित जनजाति के संबंध में किसी जाति के दावे पर विचार किया जाता है, तो जाति जांच समिति को हर मामले में मामले को संबंध परीक्षण सहित जांच करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को यांत्रिक रूप से नहीं भेजना चाहिए। संदर्भ में सतर्कता प्रकोष्ठ तभी बनाया जा सकता है जब जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट न हो।

22. हम एक और परिदृश्य पर भी विचार कर सकते हैं जो कई मामलों में पाया जाता है। ये ऐसे मामले हैं जहां आवेदक जाति पर निर्भर करता है

आवेदक को उस व्यक्ति के साथ अपना सटीक और सटीक संबंध स्थापित करना चाहिए जिसे वैधता प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा, जांच समिति द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या संबंधित जांच समिति द्वारा उचित जांच करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदक के रक्त संबंधी को वैधता प्रमाण पत्र दिया गया है। इसलिए, यदि जांच समिति ने कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में निर्णय के संदर्भ में एक वैधता प्रमाण पत्र जारी किया है, तो जांच यह होगी कि क्या जांच उक्त निर्णय पर विचार किया गया है। यदि 2000 के अधिनियम के लागू होने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो जांच समिति को यह पता लगाना होगा कि क्या संबंधित जांच

समिति ने उसमें निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ एसटी नियमों या एससी नियमों, जैसा भी मामला हो, का पालन किया था। इस सत्यापन के लिए, जांच समिति संबंधित जाति जांच एम. ए. एच. के रिकॉर्ड की मांग करके धारा 9 (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

समिति, जिसने आवेदक के रक्त संबंधी को वैधता प्रमाण पत्र जारी किया है। यदि अभिलेख नष्ट कर दिया गया है, तो जांच समिति यह पता लगा सकती है कि क्या जाति जांच समिति के निर्णय के आधार पर उचित जांच की गई है, जिसके द्वारा जाति की वैधता है।

आवेदक के रिश्तेदार को रक्त दिया गया। यदि यह स्थापित हो जाता है कि वैधता प्रमाण पत्र उचित जांच किए बिना या कारण दर्ज किए बिना दिया गया है, तो जाहिर है, जाति जांच समिति केवल रक्त संबंधी के ऐसे वैधता प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं कर सकती है।

23. किसी मामले में, जांच समिति इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि आवेदक द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

कानूनी जाँच करने के बाद। लेकिन यदि जांच समिति का विचार है कि आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित नहीं किया है कि जिस व्यक्ति को अभिलेख पर जाति वैधता प्रमाण पत्र दिया गया है, वह उसका रक्त संबंधी है, तो अनुसूचित जनजाति नियमों के नियम 12 के उप-नियम (2) के संदर्भ में, जाति जांच समिति को मामले को जांच करने के लिए भेजना होगा। सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से जांच। ऐसे मामले में, सतर्कता प्रकोष्ठ को जांच समिति द्वारा उस व्यक्ति के साथ आवेदक द्वारा दावा किए गए संबंध तक सीमित जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है जिसके पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के आधार पर जांच समिति का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह

आवेदक के रक्त संबंधी और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वैध जांच की गई है, जांच समिति को वैधता प्रमाण पत्र जारी करना होगा, भले ही आवेदक संतुष्ट न हो

आत्मीयता परीक्षण। उदाहरण के लिए, यदि यह स्थापित हो जाता है कि आवेदक के पिता या दादा को कानून के अनुसार वैध जांच करने के बाद जाति वैधता प्रमाण पत्र दिया गया है, तो जाति जांच समिति यह नहीं मान सकती है कि आवेदक के दादा या पिता, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन आवेदक अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। केवल तभी जब आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया संबंध है स्थापित नहीं होने पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य और आत्मीयता परीक्षण के परिणाम को जांच समिति द्वारा विचार में लिया जा सकता है।

24. जैसा कि एसटी नियमों के नियम 12 के उप-नियम (7) में दिया गया है, सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट निर्णायक नहीं है। यदि रिपोर्ट के आधार पर

सतर्कता प्रकोष्ठ और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य, जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जाति का दावा वास्तविक है, एक जाति वैधता [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। केवल इस आधार पर कि सतर्कता की रिपोर्ट

प्रकोष्ठ आवेदक के पक्ष में है, वैधता प्रमाण पत्र को बिना दिमाग के लागू किए यांत्रिक रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है। यदि सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट आवेदक के खिलाफ है, तो उसके जाति के दावे को केवल सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान किए बिना और उसे रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है। आवेदक को रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, जांच समिति जाति के दावे को अस्वीकार कर सकती है। किसी मामले में, जांच समिति यह निष्कर्ष भी दर्ज कर सकती है कि जाति का दावा वास्तविक है। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

एफ़िनिटी टेस्ट

माधुरी पाटिल '1 में यह माना गया है कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में, सतर्कता प्रकोष्ठ विशिष्ट नृविज्ञान और मानव विज्ञान के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विशेष जाति या जनजाति के संबंध में जातीय विशेषताएँ, देवता, अनुष्ठान, रीति-रिवाज, विवाह का तरीका, मृत्यु समारोह, शवों को दफनाने के तरीके आदि। किसी विशेष अनुसूचित जनजाति के संबंध में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे विवरण आत्मीयता परीक्षण के संचालन के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ, एक आत्मीयता परीक्षण आयोजित करते समय, उस विशेष अनुसूचित जनजाति के संबंध में समुदाय के देवताओं, रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों, विवाह के तरीके, मृत्यु समारोहों आदि के बारे में आवेदक के ज्ञान का सत्यापन करता है। अपनी प्रकृति से, इस तरह की आत्मीयता परीक्षा कभी भी निर्णायक नहीं हो सकती है। यदि आवेदक दशकों से अपने परिवार के साथ बड़े शहरी क्षेत्रों में रहा है या यदि उसका परिवार दशकों से ऐसे शहरी क्षेत्रों में रहा है, तो आवेदक को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकती है। यह सच है कि सतर्कता प्रकोष्ठ आवेदक के माता-पिता से भी पूछताछ कर सकता है। लेकिन किसी मामले में, माता-पिता भी कर सकते हैं इस कारण से अनजान रहें कि वे कई वर्षों से बड़े शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। दूसरी ओर, एक व्यक्ति विशेष जनजाति से संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन उसे उपरोक्त पहलुओं के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री शेखर नाफडे,

यह सही है जब उन्होंने प्रस्तुत किया कि आत्मीयता परीक्षण को लिटमस परीक्षण के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। हम यहां फिर से ध्यान दे सकते हैं कि आत्मीयता परीक्षण के संचालन का सवाल केवल उन मामलों में उत्पन्न होता है जहां जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं होती है।

26. एक तर्क दिया गया है कि जहां तक एससी नियमों का संबंध है, नियम 13 का खंड (डी) विशेष रूप से सतर्कता प्रकोष्ठ एम. ए. एच. के लिए प्रावधान करता है।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

एक आत्मीयता परीक्षण आयोजित करना और एसटी नियमों में ऐसा कोई समान सामग्री प्रावधान नहीं है। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि एसटी नियमों के नियम 12 का उप-नियम (4) सतर्कता अधिकारी को तथ्य एकत्र करने का आदेश देता है।

आवेदक या उसके माता-पिता की सामाजिक स्थिति के बारे में, जैसा भी मामला हो

बनो। इसलिए, उप-नियम (5) में आवेदक और उसके माता-पिता की परीक्षा का प्रावधान है। एसटी नियमों के नियम 12 के उप नियम (4) द्वारा विचारित सामाजिक स्थिति के सत्यापन के लिए, किसी दिए गए मामले में, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा आत्मीयता परीक्षण का सहारा लिया जा सकता है।

एक-दूसरे को दोषी ठहराने की जाँच समिति

परफॉर्मर्स क्लासी-न्यायिक कार्य

27. विजाकुमार 3 और आनंद के मामलों में निर्णय लेने से पहले हमें उनमें से एक द्वारा दिए गए तर्क से निपटने की आवश्यकता है। हस्तक्षेप करता है कि जांच समिति एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण नहीं है। उक्त निवेदन दयारामो के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर आधारित है। पैराग्राफ 35 में, दयारामो के मामले में निर्णय इस प्रकार है:

" 35. जाँच समिति अदालत या न्यायाधिकरण की तरह एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक निकाय है जो तथ्यों की पुष्टि करता है, एक विशिष्ट दावे (जाति की स्थिति) की जांच करता है और यह पता लगाता है कि दावा की गई जाति/आदिवासी स्थिति सही है या नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों के किसी भी अन्य निर्णय की तरह, जांच समिति के आदेश भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती देने के लिए खुले हैं। अपीलों और आगे की अपीलों के प्रावधानों के साथ दीवानी मुकदमों की अनुमति देने से योजना ही विफल हो जाएगी और उन बुराइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिन्हें यह न्यायालय मिटाना चाहता था। जैसा कि इस न्यायालय ने पाया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बड़ी संख्या में सीटें या पद फर्जी तरीके से छीन लिए जा रहे थे

अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवार और

अनुसूचित जनजाति, इस न्यायालय ने संविधान का निर्देश दिया

ऐसी जांच समितियाँ, एक त्वरित व्यवस्था प्रदान करने के लिए,

किसी भी कानून या गलत के उचित सत्यापन के लिए एक कानूनी ढाँचे के अभाव में प्रभावी और प्रभावी उपचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति के संबंध में दावे। यह पूरी योजना

माधुरी पाटिल [(1994) 6 एस. सी. सी. 241: 1994 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1349: (1994) 28 ए. टी. सी. 259] केवल तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित विधानमंडल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति के दर्जे के दावों के सत्यापन और [2023] 3 एस. सी. आर. जारी करने के संबंध में एक उचित कानून नहीं बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाति प्रमाणपत्र, या जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के संबंध में

आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा पहले से प्राप्त,

इस तरह के जाति प्रमाणपत्रों पर भरोसा करना।

(जोर

दिया गया)

28. हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यह न्यायालय उक्त मामले में काम कर रहा था।

मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न एक मामले के साथ निर्णय जहाँ अस्तित्व में कोई कानून नहीं था जो कुमारी माधुरी पाटिल के मामले 1 द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को कवर करता था। अतः इन टिप्पणियों में

उक्त निर्णय कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में निर्णय के तहत बनाई जाने वाली जांच समिति की शक्तियों के संदर्भ में है। दयाराम और जय चित्र के मामलों में, इस न्यायालय ने 2000 के अधिनियम या किसी अन्य पर लागू होने वाले समान अधिनियम पर विचार नहीं किया है।

राज्य। 2000 के अधिनियम के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नियमों के संयुक्त अध्ययन पर, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि

समिति केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करती है। जाँच 2000 के अधिनियम के तहत समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की विभिन्न शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इन शक्तियों

इसमें किसी भी गवाह की उपस्थिति को लागू करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, गवाहों या दस्तावेजों आदि की परीक्षा के लिए आयोग जारी करने की शक्ति शामिल है। 2000 के अधिनियम की योजना और एससी और एसटी दोनों नियमों में जांच समिति के लिए, यदि आवश्यक हो, शपथ पर आवेदक की जांच करने, गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और दस्तावेजों और रिकॉर्ड आदि के लिए बुलाने के बाद, आवेदक के जाति दावे पर जांच करने का प्रावधान है। उम्मीद की जाती है कि जांच समिति जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगी। इस प्रकार, जांच समिति के पास एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के सभी गुण हैं।

आनंद

29. अब

हम विजाकुमार 3 के मामले में निर्णय पर आते हैं। ए.

विजाकुमार 3 के मामले में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि दो माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न एक जनजाति के दावे के मुद्दे पर विचार किया। निर्णय के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उक्त निर्णय में एसटी नियमों का कोई संदर्भ भी नहीं है। न्यायालय का ध्यान नियम 12 के उप-नियम (2) की ओर नहीं खींचा गया था, जिसमें कहा गया है कि मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को तभी भेजा जा सकता है जब जांच की जाए।

समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं है।

एमएएच। आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

2000 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ एससी और एसटी नियमों का उल्लेख किए बिना, विजाकुमार के मामले 3 के पैराग्राफ 9 में यह माना गया है कि:

" 9. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम हैं

माना जाता है कि इसमें शायद ही कोई योग्यता है

अपीलार्थी की ओर से उठाई गई दलीलें। आत्मीयता परीक्षण

सतर्कता अधिकारी के साथ-साथ जांच समिति द्वारा पूरा किया गया था। प्रमाणपत्र को दो चरणों में तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही साबित होने के बाद ही मान्य किया जाना चाहिए; सबसे पहले, स्तर पर।

जारी करने का और दूसरा, सत्यापन के चरण में। यदि यह इनमें से किसी भी चरण में आत्मीयता परीक्षण में विफल हो जाता है, तो प्रमाण पत्र की वैधता को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2000 के अधिनियम और नियमों पर विचार नहीं किया गया था, विजाकुमार 3 के मामले में निर्णय निश्चित रूप से एक निर्णय नहीं है।

इस प्रस्ताव के लिए बाध्यकारी उदाहरण है कि प्रत्येक मामले में, जांच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजकर आत्मीयता परीक्षण का सहारा लेना आवश्यक है।

30. पैराग्राफ 4 और 5 में आनंद के मामले में निर्णय

विशेष रूप से एसटी नियमों के नियम 11 और 12 (2) को संदर्भित करता है। पैराग्राफ 22 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 22. पूर्व में निकाले गए पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि जाति के दावे की वास्तविकता पर न केवल दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच पर विचार किया जाना चाहिए, बल्कि आत्मीयता परीक्षण पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक के मानवशास्त्रीय और जातीय लक्षण आदि शामिल होंगे।

हालाँकि, एक पूर्ण नियम निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है, जिसे जाति के दावे की जांच करने के लिए यंत्रवत रूप से लागू किया जा सकता है। फिर भी, हम महसूस करते हैं कि निम्नलिखित व्यापक मापदंड हो सकते हैं

जाति के दावे से निपटने के दौरान ध्यान में रखा जाए:

दस्तावेजी साक्ष्य से निपटने के दौरान, अधिक निर्भरता

(i)

स्वतंत्रता पूर्व दस्तावेजों पर रखा जा सकता है क्योंकि वे पद की तुलना में जाति की स्थिति की घोषणा के लिए उच्च स्तर का संभावित मूल्य प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता दस्तावेज। यदि आवेदक स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी है, तो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य की

उपलब्धता मुश्किल हो जाती है, लेकिन वास्तव में उसके दावे को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, केवल यह तथ्य कि वह स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी हैं, [2023] 3 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक के पक्ष में संदेह का कुछ लाभ हो सकता है -

दिया गया। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि संदेह की स्थिति में

किसी दस्तावेज़ की विश्वसनीयता, उसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए

मौखिक साक्ष्य का आधार, जिसके लिए एक अवसर है

आवेदक को दिया जाए;

आत्मीयता परीक्षण को लागू करते समय, जो इस पर केंद्रित है

अनुसूचित जनजाति के साथ जातीय संबंध, ए

सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा। कुछ दशक

पहले, जब जनजातियाँ कुछ हद तक प्रतिरक्षित थीं

उनके आसपास हो रहा सांस्कृतिक विकास,

आत्मीयता परीक्षण एक निर्धारक कारक के रूप में काम कर सकता है।

हालाँकि, प्रवास, आधुनिकीकरण और

अन्य समुदायों, इन समुदायों के साथ संपर्क करें

नए लक्षणों को विकसित करने और अपनाने की प्रवृत्ति होती है जो नहीं भी हो सकते हैं

अनिवार्य रूप से पारंपरिक विशेषताओं के साथ मेल खाते हैं

जनजाति से। इसलिए, आत्मीयता परीक्षण नहीं हो सकता है

लिंक स्थापित करने के लिए एक लिटमस परीक्षण के रूप में माना जाता है

अनुसूचित जनजाति वाला आवेदक। फिर भी,

एक आवेदक द्वारा दावा कि वह एक अनुसूचित का हिस्सा है

जनजाति और उस तक विस्तारित लाभ का हकदार है

जनजाति को जमीन पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है
जनजाति की विशिष्टता से मेल नहीं खाते हैं

कि उनके वर्तमान लक्षण उनकी

मानवशास्त्रीय और नृजातीय लक्षण, देवता, अनुष्ठान,
समारोह,

रीति-रिवाज, विवाह का तरीका, मृत्यु

शवों को दफनाने की विधि, आदि। इस प्रकार, आत्मीयता
दस्तावेजी की पुष्टि करने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है
साक्ष्य और अस्वीकार करने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए एक दावा "।
(जोर दिया गया)

आने के लिए पहले भी इसी तरह के कारण दर्ज किए हैं
कि आत्मीयता परीक्षण हमेशा अनिवार्य नहीं होगा और/या
आनंद 1 के मामले में निर्णय का आलेख 19 दोहराता है
कि सतर्कता प्रकोष्ठ जांच का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब समिति द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट न
हो। इस पहलू पर, हम निर्णय का उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं।
जिला कलेक्टर, सतारा 'के मामले में। यह निर्णय हम में से एक (संजय किशन कौल, जे.) द्वारा लिया गया है
जो एमएएच में एक निर्णय बनाता है।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

एसटी नियमों और विशेष रूप से नियम 12 का गहन विश्लेषण। पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“ 9.

.....

.....

... ..

उपरोक्त नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि सतर्कता प्रकोष्ठ को परिकल्पित भूमिका की तुलना में प्रतिबंधित किया गया था

माधुरी पाटिल मामले में [माधुरी पाटिल बनाम। कॉम. , जनजातीय

विकास, (1994) 6 एससीसी 241: 1994 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1349],

समिति हर मामले में नहीं थी, लेकिन केवल अगर जांच समिति दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं थी

आवेदक द्वारा प्रस्तुत "।

(जोर

दिया गया)

32. इसलिए, जैसा कि पहले देखा गया है, के मामले में निर्णय

विजाकुमार 3 को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जो एक कानूनी सिद्धांत को निर्धारित करता है कि जाति के दावे के सत्यापन के हर मामले में, जाति जाँच समिति को मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजने का आदेश दिया गया है। चूंकि एसटी नियमों की योजना के तहत, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा आत्मीयता परीक्षण आयोजित किया जाना है, इसलिए आत्मीयता परीक्षण आयोजित करने का सवाल तभी उत्पन्न होगा जब मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजने का मामला बनाया जाएगा। यदि जाँच समिति, जाँच करने के बाद, मामले को सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजे बिना, अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट हो जाती है, तो जाति जाँच समिति के अधीन है -

जाति प्रमाणपत्र को वैधता प्रदान करने का आदेश। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी मामले में, जांच समिति द्वारा एक सीमित जांच का आदेश दिया जा सकता है सतर्कता प्रकोष्ठ। उदाहरण के लिए, यदि कोई आवेदक अपने रक्त संबंधी को दिए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहा है और जांच समिति, यह पता लगाने के बाद कि प्रमाण पत्र उचित जांच के बाद जारी किया गया है, अनुरोध किए गए संबंध के बारे में संदेह पैदा करता है, तो वह सतर्कता प्रकोष्ठ को केवल संबंध के बारे में जांच करने का निर्देश दे सकता है।

33. अब हम शिल्पा विष्णु के विवादित निर्णय पर आते हैं।

ठाकुर का मामला 2. पूर्ण पीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किए गए प्रश्न पैराग्राफ 4 में हैं जो इस प्रकार हैं:

" (i) जाति निर्धारित करने में सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति का दावा दस्तावेजी साक्ष्य हो या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में

अदालत ने कहा, "मानवशास्त्रीय आधार और जातीय संबंध";

और इस तरह के एक के लिए "महत्वपूर्ण आत्मीयता परीक्षण" प्रासंगिक और सटीक है

निर्णय?

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ए) ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

किसी विशेष जाति से संबंधित होने का दावा करने से संतुष्ट होता है

आवश्यकता, उदाहरण के लिए, "ठाकुर" के मामले में, यदि सभी

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए/दाखिल किए गए और उन पर भरोसा किए गए दस्तावेज उनकी जाति को "ठाकुर" के रूप में दर्शाते हैं, फिर "महत्वपूर्ण आत्मीयता परीक्षण" के संदर्भ में जाति के दावे को मान्य किए बिना, क्या जाति का दावा करना चाहिए।

प्रमाणित किया जाए या नहीं?

(ख) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष जाति के दावे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, वह दावा कर सकता है।

"महत्वपूर्ण आत्मीयता परीक्षण" के आधार पर जांच की जाए, और

वैधता प्रमाण पत्र जारी किया जाए?

(ग) जहाँ एक व्यक्ति जो किसी विशेष जाति से संबंधित होने का दावा करता है, उसके पक्ष में कुछ दस्तावेज हैं और/या महत्वपूर्ण आत्मीयता परीक्षण को आंशिक रूप से संतुष्ट करता है, तो क्या दावा प्रमाणित किया जा सकता है और उम्मीदवार हकदार है।

उसके जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया जा रहा है? " *

34. पूर्ण पीठ के निष्कर्ष पैराग्राफ 40 में दर्ज किए गए हैं। पैराग्राफ 40 के खंड (i) में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दर्ज किया है कि नियम 12 (2) के तहत, जांच समिति, यदि वह प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो उसे प्रस्तुत करना होगा

विद्यालय, गृह और अन्य पूछताछ आयोजित करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को आवेदन। पूर्ण पीठ यह निर्धारित नहीं करती है कि हर मामले में जहां जांच की जाती है समिति अनुसूचित जनजाति के दावे पर विचार कर रही है, सतर्कता प्रकोष्ठ को एक संदर्भ दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ 40 के खंड (ii) (ए) में, पूर्ण पीठ ने दर्ज किया है कि जांच समिति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए -

साक्ष्य का पूरा हिस्सा, इस सवाल के साथ कि क्या आवेदक ने आत्मीयता परीक्षण को संतुष्ट किया है। जैसा कि पहले कहा गया था, आत्मीयता परीक्षण का सहारा लेने का सवाल तभी उठेगा जब मामला सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। वास्तव में, पैराग्राफ 40 के खंड (बी) में, पूर्ण पीठ का मानना है कि भले ही किसी आवेदक के पास कोई दस्तावेजी सबूत न हो, लेकिन यह वास्तव में जाति के दावे को अमान्य नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले में नियम 12 का उप-नियम (2) लागू होगा और सतर्कता प्रकोष्ठ को आत्मीयता परीक्षण सहित एक जांच करनी होगी। ऐसे में भी

मामले में, आत्मीयता परीक्षण किसी भी तरह से निर्णायक नहीं होगा जैसा कि आनंद के मामले में पैराग्राफ 20 के खंड (2) में आयोजित किया गया है। उसी पैराग्राफ के खंड (सी) में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि भले ही आवेदक अभिलेख पर साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर आत्मीयता परीक्षण को आंशिक रूप से संतुष्ट करता है, लेकिन जांच समिति के पास एम. ए. एच. को मान्य करने की शक्ति है।

आदिवासी ठाकुर जमात स्वरक्षण समिति बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

दावा करें। इस प्रकार, सम खंड (सी) इस आधार पर आगे बढ़ता है कि आत्मीयता परीक्षण निर्णायक नहीं है।

35. आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 40 को समग्र रूप से पढ़ते हुए,

हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आत्मीयता परीक्षण की निर्णायक प्रकृति के बारे में पूर्ण पीठ द्वारा एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है। निष्कर्ष नहीं हो सकता है

इसका मतलब यह समझा जाता है कि सतर्कता प्रकोष्ठ का संदर्भ और प्रत्येक मामले में आत्मीयता परीक्षण का संचालन अनिवार्य है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में हमने जो कारण दर्ज किए हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। आक्षेपित निर्णय में यह अवलोकन कि "आत्मीयता परीक्षण दावे की शुद्धता के निर्धारण का एक अभिन्न अंग है"

निष्कर्ष

36. इस प्रकार, निष्कर्ष निकालने के लिए, हम मानते हैं कि:

(अ)

केवल तभी जब जाँच समिति जाँच करने के बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं है,

मामला सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा जा सकता है। संदर्भ देते समय सतर्कता प्रकोष्ठ का मामला, जाँच समिति को करना चाहिए

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करें कि यह है आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट नहीं होना।

उठें।

जिन कारणों को हमने दर्ज किया है, उनमें आत्मीयता परीक्षण नहीं हो सकता है।

(ख)

किसी भी तरह से निर्णायक बनें। जब एक आत्मीयता परीक्षण आयोजित किया जाता है

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा, सभी के साथ परीक्षण का परिणाम

अभिलेख पर संभावित मूल्य वाली अन्य सामग्री होगी

जाँच समिति द्वारा विचार में लिया जाना

जाति वैधता दावा तय करने के लिए; और

(ग)

किसी जाति या जनजाति के दावे की शुद्धता का निर्धारण
हर मामले में।

37. हम रजिस्ट्री को अपील/एस. एल. पी. प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।

हमारे द्वारा उत्तर दिए गए संदर्भ के आलोक में उसी पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त पीठा

अंकित ज्ञान

संदर्भ

ने जवाब दिया।

(सहायक: वरुण धोंड और महेन्द्र यादव, एलसीआरए)